आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 20.05.2025

समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, तीर्थयात्रा के पहले बीस दिनों में दस लाख श्रद्धलुओं ने किये चारधाम दर्शन।
- चमोली जिले के स्थानीय किसानों द्वारा भारतीय सेना को पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति शुरू, सेना की अग्रिम चौकियों तक भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पाद, स्थानीय स्तर पर कराए जाएंगे उपलब्ध।
- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर समय पर जारी करने के निर्देश दिए।
- **और,** देहरादून जिले में सफाई कर्मियों व उनके आश्रितों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तीन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

चारधाम यात्रा

प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तीस अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र तीर्थयात्रा में महज बीस दिनों में ही दस लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक केदारनाथ में लगभग चार लाख, बदरीनाथ में ढाई लाख, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तीन लाख पैंसठ हजार को पार कर गई है।

राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सभी धामों पर स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल मेडिकल यूनिट, और 108 एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की गई हैं। तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, और विश्राम की उचित व्यवस्था की गई है।

इस बार यात्रा के दौरान तीर्थाटन को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निगरानी तंत्र भी सक्रिय है। ट्रैफिक प्रबंधन, मौसम अलर्ट और राहत टीमों को धामों और यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके।

आपूर्ति / रोजगार

चमोली जिले से भारतीय सेना को स्थानीय किसानों द्वारा पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की पहल शुरू हो गई है। इसके तहत अब सेना की अग्रिम चौकियों तक भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पाद, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने कल जोशीमठ से माणा और मलारी पोस्ट के लिए पोल्ट्री उत्पादों की पहली खेप रवाना की।

पशुपालन विभाग की इस योजना के तहत पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य और स्थायी बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

पूर्व में पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच हुए समझौते के बाद से स्थानीय पशुपालकों को नए बाजार मिलने शुरू हुए हैं। अब सेना को भी स्थानीय स्तर पर भेड़, बकरी और कुक्कुट की आपूर्ति का रास्ता खुला है, जिससे वाइब्रेंट गांवों के पशुपालकों को आय का नया जरिया मिलेगा। इससे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पलायन की समस्या पर भी रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया है, जो सीमावर्ती गांवों के लिए स्थायी बाजार और रोजगार सुनिश्चित करेगा।

वित्त आयोग

16वें वित्त आयोग की टीम ने कल को देहरादून में नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सुझाव लिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने तीर्थाटन, पर्यटन, स्वच्छता, पार्किंग, सीवरेज, आपदा प्रबंधन और ग्रीन बोनस जैसे विषयों पर राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग उठाई।

शहरी निकायों ने तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट बढ़ाने की बात कही। मेयरों का कहना था कि आबादी और पर्यटन के दबाव के कारण सफाई, कूड़ा निस्तारण और पार्किंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए अधिक फंड की जरूरत है। वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्रफल के अनुसार बजट आवंटन की मांग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता और आपदा से जुड़ी योजनाओं के लिए अलग बजट देने की बात कही।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य को विशेष आर्थिक मदद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए उसे ग्रीन बोनस और कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। साथ ही, पलायन रोकने, महिला कुटीर उद्योग बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी राज्य को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

जनसुनवाई

देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन और जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 145 शिकायतें मिलीं, जिनमें अधिकतर भूमि संबंधी थीं। इसके अलावा आपसी विवाद, आर्थिक सहायता, सफाई, पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन, ऋण माफी आदि से भी शिकायतें आईं।

मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों में जांच लंबी हो रही है, शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी भी दी जाए। उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम व उप जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा। भूमि सीमांकन की शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

निर्देश

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर समय पर जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र समय पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले सकें। विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समर्थ पोर्टल के संचालन की जिम्मेदारी शासन से हटाकर राजकीय विश्वविद्यालयों को सौंपने के निर्देश भी दिए।

डॉ. रावत ने कहा कि अब विश्वविद्यालय स्वयं समर्थ पोर्टल का संचालन करेंगे, जिससे राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश से लेकर शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष समर्थ पोर्टल को लेकर कई समस्याएं सामने आई थीं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर एक सप्ताह के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति– डीपीसी कराई जाए। साथ ही उन्होंने विभिन्न संकायों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

विशेष शिविर

देहरादून जिले में मैनुअल स्कैवेंजर्स, सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तीन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर इन शिविरों का आयोजन रेखीय विभागों की ओर से किया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि 27 मई को चुक्खूवाला, 31 मई को इंद्रेश नगर और 3 जून को वाल्मीकि बस्ती ऋषिकेश में यह शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में समाज कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, उद्योग, बैंक, श्रम विभाग और नगर निगम समेत कई विभाग मौजूद रहेंगे।

शिविरों में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग वितरण, कुपोषण सुधार, मातृ वंदना योजना, महालक्ष्मी किट, पोषण किट, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, स्वरोजगार योजनाओं और बीमा जैसी कई सेवाएं दी जाएंगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से शिविर को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया और सफाई कर्मियों व उनके परिवारों से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने की अपील की है।

ई–जीरो एफआईआर

गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई–फोर–सी) ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नई ई–जीरो एफआईआर पहल की है। दिल्ली में यह नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 पर दर्ज दस लाख रुपये से अधिक राशि के साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि इस नई प्रणाली से साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई और जांच संभव होगी। इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।

जागरूकता शिविर

पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट के राजकीय इंटर कालेज भटेड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र–छात्राओं को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, पॉक्सो सहित अन्य कई कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर वक्ताओं ने कहा कि हर व्यक्ति को कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि जनता जागरूक होगी तभी अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। शिविर में 72 छात्र–छात्राओं ने हिस्सा लिया।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

16वें वित्त आयोग से राज्य के लिए ग्रीन बोनस की मांग की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नवोदय टाइम्स लिखता है– ग्रीन बोनस मिले, कर वितरण का आधार बने क्षेत्रफल। इसी खबर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है– राज्य को वन संरक्षण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग आबादी के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। दैनिक जागरण ने लिखा है– मुख्यमंत्री धामी ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष विस्तार से रखा राज्य का पक्ष। अमर उजाला लिखता है– पर्यावरणीय सेवाओं की लगात के हिसाब से दें क्षतिपूर्ति।

उत्तराखंड के मदरसों में छात्र–छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा।

इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– प्रदेश के मदरसों में पढ़ाया जाएगा'' ऑपरेशन सिंदूर''।

उत्तराखंड में भीख मांगता नहीं दिखेगा एक भी बच्चा। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है– राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास पॉलिसी लागू हुई तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा बेहतर जीवन का मौका, ड्राफ्ट को मिल चुकी है स्वीकृति।